SAFALTA CLASS™

An Initiative by अमर उजाला

CTET - P-2

SST

INDIAN POLITY

BY – SUJEET BAJPAI SIR

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

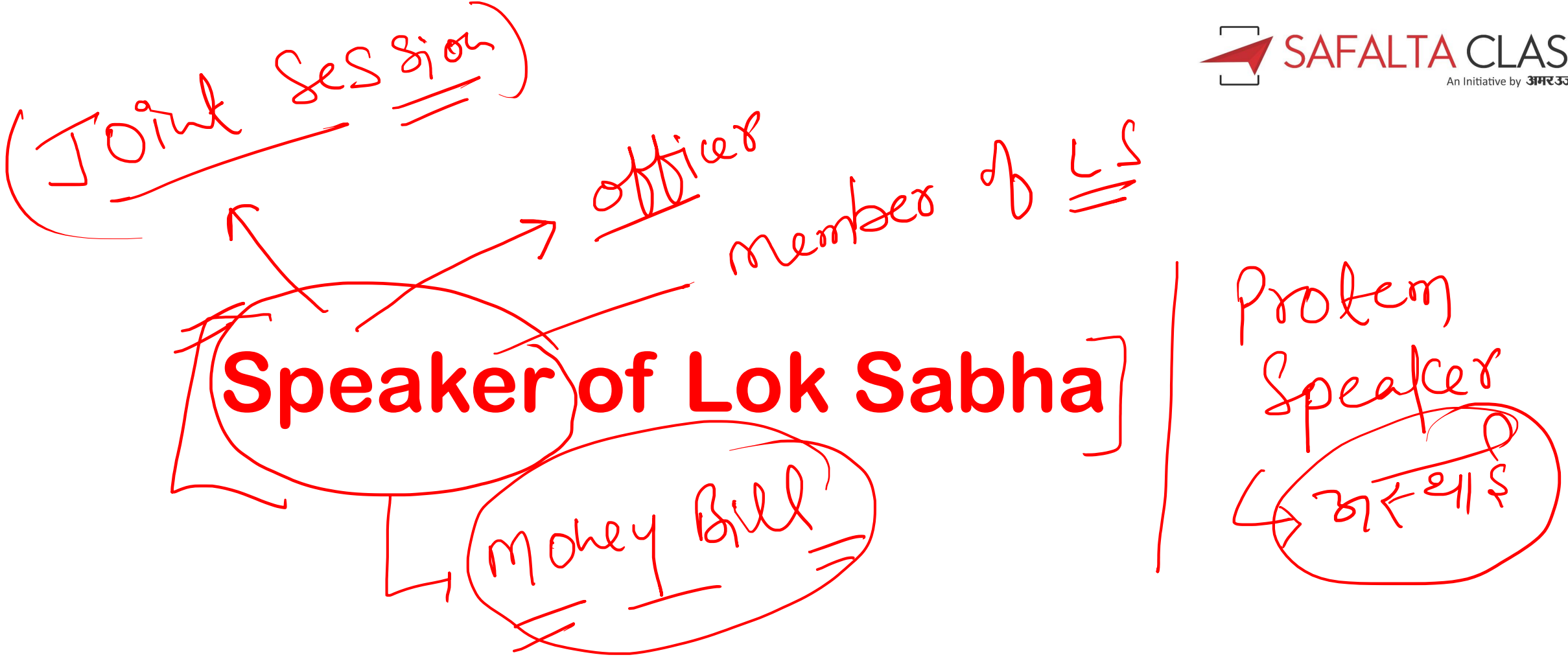

G V Mavalankar and Ananthasayanam Ayyangar had the distinction of being the first Speaker and the first Deputy Speaker (respectively) of the Lok Sabha.

G V Mavalankar also held the post of Speaker in the Constituent Assembly (Legislative) as well as the provisional Parliament.

He held the post of Speaker of Lok Sabha continuously for one decade from 1946 to 1956.

जी वी मावलंकर और अनंतस्यम अयंगर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष और प्रथम डिप्टी स्पीकर (क्रमश) होने का गौरव प्राप्त हुआ।

जी वी मावलंकर ने संविधान सभा (विधान) के साथ-साथ अनंतिम संसद में अध्यक्ष का पद भी संभाला ।

उन्होंने 1946 से 1956 तक लगातार एक दशक तक लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखा।

Election and Tenure

The Speaker is elected by the Lok Sabha from amongst its members (as soon as may be, after its first sitting).

The date of election of the Speaker is fixed by the President.

Usually, the Speaker remains in office during the life of the Lok Sabha.

चुनाव और कार्यकाल लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से (जैसे ही हो सकता है, अपनी पहली बैठक के बाद) से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है ।

अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।

आमतौर पर लोकसभा के जीवन काल में अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं।

Role, Powers and Functions of Speaker:

- **He adjourns the House or suspends the meeting in absence of a quorum.**
- **The quorum to constitute a meeting of the House is one-tenth of the total strength of the House.**
- वह सदन स्थगित कर देते हैं या कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर देते हैं।
- सदन की बैठक गठित करने का कोरम सदन की कुल संख्या का दसवां हिस्सा है।

- He does not vote in the first instance. But he can exercise a casting vote in the case of a tie.
- In other words, only when the House is divided equally on any question, the Speaker is entitled to vote.
- Such vote is called casting vote, and its purpose is to resolve a deadlock.

वह पहली बार में वोट नहीं देते । लेकिन वह टाई के मामले में कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकते हैं ।

दूसरे शब्दों में, जब सभा किसी भी प्रश्न पर समान रूप से विभाजित होती है, तभी अध्यक्ष को मतदान करने का अधिकार होता है ।

इस तरह के वोट को कास्टिंग वोट कहा जाता है, और इसका उद्देश्य एक गतिरोध को सुलझाना है ।

- **He presides over a joint setting of the two Houses of Parliament.**
- **Such a sitting is summoned by the President to settle a deadlock between the two Houses on a bill.**

- वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त ~~सेटिंग~~ की अध्यक्षता करते हैं ।
- इस तरह की बैठक में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को निपटाने के लिए बुलाया जाता है ।

Joint Sitting of Two Houses

1. if the bill is rejected by the other House;
2. if the Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill; or
3. if more than six months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other House without the bill being passed by it.

दो सदनों की संयुक्त बैठक

1. यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है;

2. यदि सदनों ने अंततः विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में असहमति व्यक्त की है; या

3. यदि दूसरे सदन दवारा बिल प्राप्त करने की तारीख से छह महीने से अधिक का समय बीत चुका है तो बिल पारित किए बिना।

Since 1950, the provision regarding the joint sitting of the two Houses has been invoked only thrice. The bills that have been passed at joint sittings are:

1. Dowry Prohibition Bill, 1960.
2. Banking Service Commission (Repeal) Bill, 1977.
3. Prevention of Terrorism Bill, 2002.

1950 के बाद से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रावधान केवल तीन बार लागू किया गया है। संयुक्त बैठकों में पारित किए गए विधेयक हैं:

1.दहेज निषेध विधेयक, 1960।
2. बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977।
3. आतंकवाद निरोधक विधेयक, 2002।

- He decides whether a bill is a money bill or not and his decision on this question is final.
- When a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation and presented to the President for assent, the Speaker endorses on the bill his certificate that it is a money bill.

वह तय करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं और इस सवाल पर उनका फैसला अंतिम है।

जब एक धन विधेयक को सिफारिश के लिए राज्यसभा में प्रेषित किया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो अध्यक्ष विधेयक का समर्थन करते हैं कि यह एक धन विधेयक है ।

Sessions of Parliament

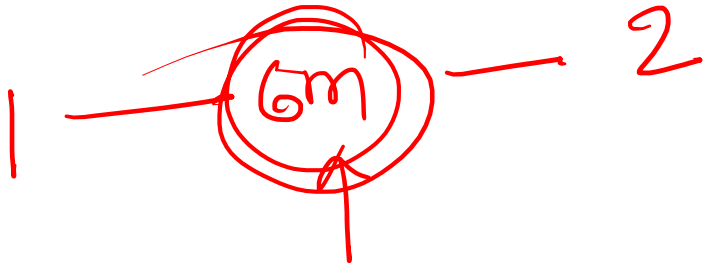

Summoning

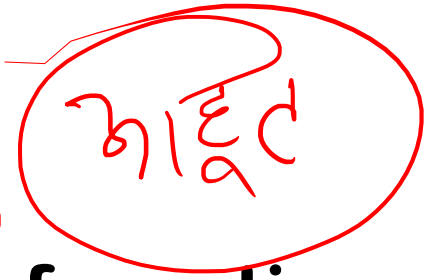

The president from time to time summons each House of Parliament to meet. But, the maximum gap between two sessions of Parliament cannot be more than six months.

In other words, the Parliament should meet at least twice a year.

संसद का सत्र:

By President

Summoning :

राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाते हैं। लेकिन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर छह महीने से ज्यादा नहीं हो सकता।

दूसरे शब्दों में, संसद की बैठक वर्ष में कम से दो बार होनी चाहिए ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Longest Session

There are usually three sessions in a year, viz,

1. the Budget Session (February to May);

2. the Monsoon Session (July to September); and

3. the Winter Session (November to December).

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Adjournment

By Speaker

A session of Parliament consists of many meetings. Each meeting meeting of a day consists of two sittings, that is, a morning sitting from 11 am to 1 pm and post-lunch sitting from 2 pm to 6 pm.

A sitting of Parliament can be terminated by adjournment or adjournment sine die or prorogation or dissolution (in the case of the Lok Sabha).

स्थगन

संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती हैं। एक दिन की हर मीटिंग मीटिंग में दो मीटिंग होती हैं, यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठकर लंच के बाद दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बैठे रहते हैं।

संसद की बैठक को स्थगन या स्थगन या कार्यवाही या विघटन (लोकसभा के मामले में) द्वारा समाप्त किया जा सकता है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Prorogation

सत्रावसान

The presiding officer (Speaker or Chairman) declares the House adjourned sine die, when the business of a session is completed.

Within the next few days, the President issues a notification for prorogation of the session.

सत्रावसान

पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या अध्यक्ष) सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हैं, जब किसी सत्र का कामकाज पूरा हो जाता है ।

अगले कुछ दिनों के भीतर राष्ट्रपति सत्र के सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी करते हैं ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Head of executive कार्यपालिका

→ Head of State

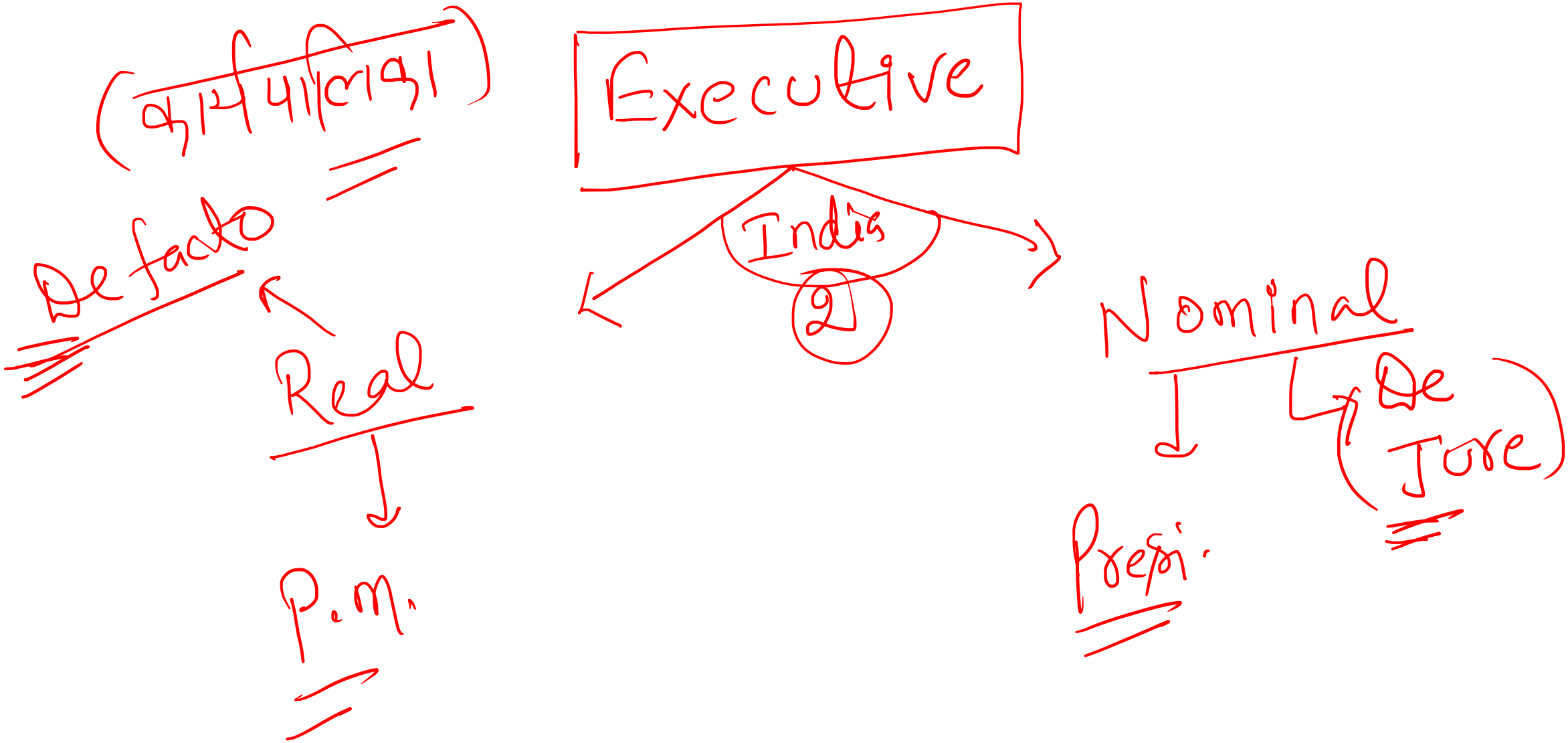

(कार्यपालिका)
Executive
India
2
De facto
Real
P.M.
Nominal
(De Jure)
Presi.

Articles 52 to 78 in Part V of the Constitution deal with the Union executive.

The Union executive consists of the Presi-dent, the Vice-President, the Prime Minister, the council of ministers and the attorney general of India.

संविधान के भाग पांच में अनुच्छेद 52 से 78 संघ कार्यकारिणी के साथ सौदा।

संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

The President is the head of the Indian State. He is the first citizen of India and acts as the symbol of unity, integrity and solidarity of the nation.

राष्ट्रपति भारतीय राज्य के प्रमुख हैं। वह भारत के प्रथम नागरिक हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं।

Indirect
अप्रत्यक्ष

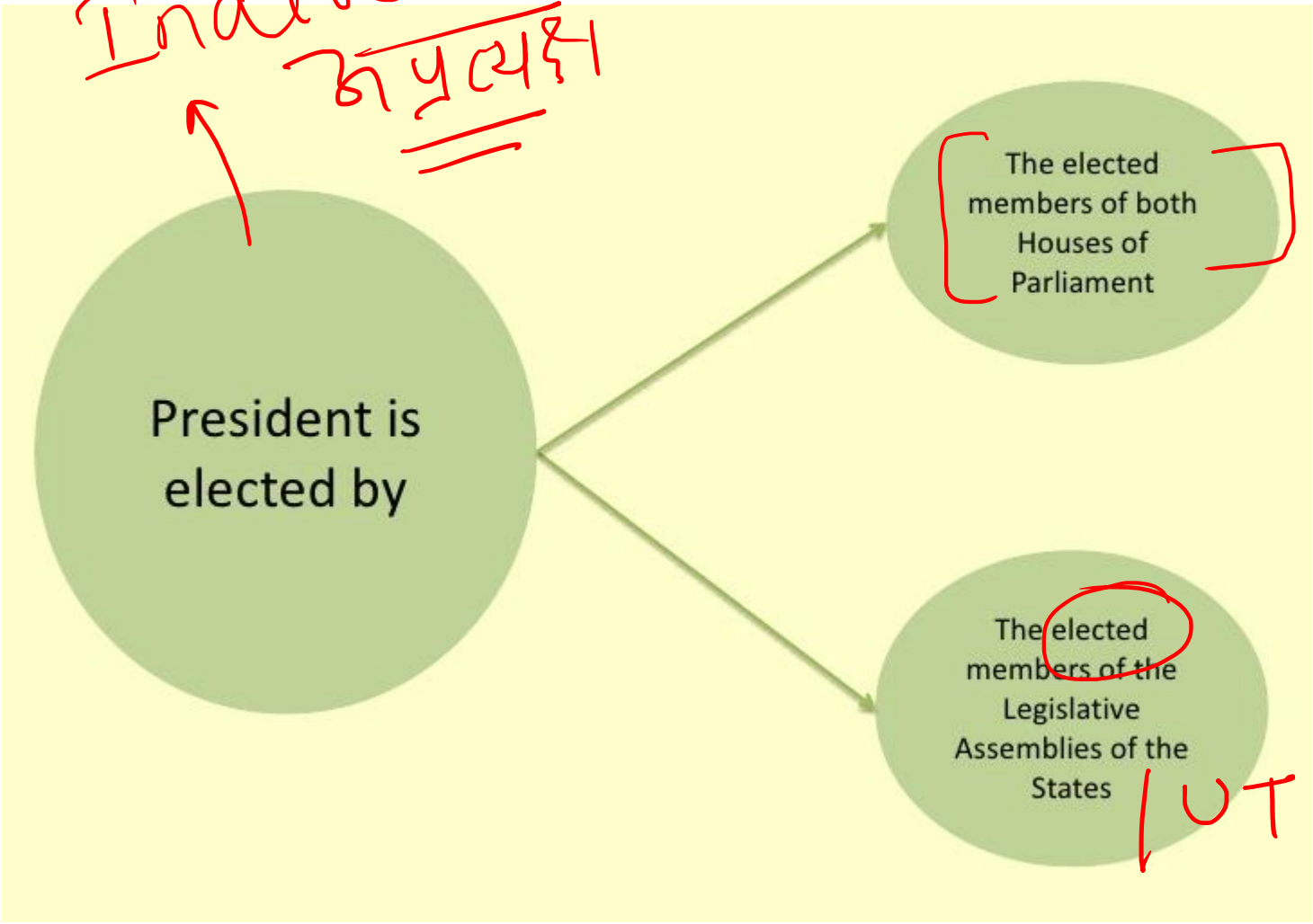

Not Nominated
X

The President is elected not directly by the people but by members of electoral college consisting of:

1. the elected members of both the Houses of Parliament;

2. the elected members of the legislative assemblies of the states; and

3. the elected members of the legislative assemblies of the Union Territories of Delhi, Jammu & Kashmir and Puducherry.

राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है जिसमें शामिल हैं:

1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य;
2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य; और
3. दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

The President's election is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting is by secret ballot.

This system ensures that the successful candidate is returned by the absolute majority of votes.

राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है ।

यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सफल उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत से वापस किया जाए ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

If the election of a person as President is declared void by the Supreme Court, acts done by him before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated and continue to remain in force.

यदि राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की ऐसी घोषणा की तारीख से पहले उसके द्वारा किए गए कृत्यों को अमान्य नहीं किया जाता है और वह लागू रहता है ।

Qualifications for Election as President

A person to be eligible for election as President should fulfil the following qualifications:

1. He should be a citizen of India.
2. He should have completed 35 years of age.
3. He should be qualified for election as a member of the Lok Sabha.
4. He should not hold any office of profit under the Union government or any state government.

राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना चाहिए:

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी।
3. उसे लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।
4. उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए।

The nomination of a candidate for election to the office of President must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders.

Every candidate has to make a security deposit of Rs 15,000 in the Reserve Bank of India.

राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावक के रूप में कम से ५० निर्वाचकों और ५० निर्वाचकों को सेटर के रूप में सदस्यता लेनी चाहिए ।

हर उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी।

The oath of office to the President is administered by the Chief Justice of India and in his absence, the seniormost judge of the Supreme Court available.

राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है और उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध होते हैं ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

महाभियोग - Art-61

Base ⇒ उल्लंघन Violation of Consti.

(अर्द्ध न्यायिक)
Quasi Judicial Process

The President can be removed from office by a process of impeachment for 'violation of the Constitution'.

However, the Constitution does not define the meaning of the phrase 'violation of the Constitution'.

संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है ।

हालांकि, संविधान में संविधान के उल्लंघन के वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है ।

Procedure of Impeachment

1. A written notice signed by more than **1/4th of the total number of members of the House**(any) is submitted. Once it is received, after 14days a Resolution is moved.

2. The Resolution is passed by majority i.e. more than **2/3rd of the total members of the House**.

3 & 4
- The **charge is sent to the other house for investigation**. President needs to be present for the investigation.
- After the investigation, **if the charge is proved right** and passed by **2/3rd of the total members of the house** (which investigated) then the **President is removed**.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Vacancy in the President's Office

A vacancy in the President's office can occur in any of the following ways:

1. On the expiry of his tenure of five years.
2. By his resignation.
3. On his removal by the process of impeachment.

राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति राष्ट्रपति कार्यालय में एक रिक्ति निम्नलिखित तरीकों में से किसी में हो सकती है:

1. पांच साल का उनका कार्यकाल समाप्त होने पर।
2. उनके इस्तीफे से ।
3. महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें हटाने पर ।

4. By his death.

(So far two Presidents, Dr Zakir Hussain and Fakhruddin Ali Ahmed, have died during their term of office.)

5. Otherwise, for example, when he becomes disqualified to hold office or when his election is declared void.

Disputes Related to Presi. elec. → सुप्रीम कोर्ट

4. उसकी मृत्यु से। (अब तक दो राष्ट्रपतियों डॉ जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो चुकी है ।

5. अन्यथा, उदाहरण के लिए, जब वह पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाता है या जब उसका चुनाव शून्य घोषित हो जाता है।

If the office falls vacant by resignation, removal, death or otherwise, then election to fill the vacancy should be held within six months from the date of the occurrence of such a vacancy.

यदि पद त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्यथा से खाली हो जाता है, तो रिक्ति को भरने के लिए चुनाव ऐसी रिक्ति की घटना की तारीख से छह महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए ।

When the sitting President is unable to discharge his functions due to absence, illness or any other cause, the Vice-President discharges his functions until the President resumes his office.

जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन तब तक करते हैं जब तक कि राष्ट्रपति अपना पद शुरू नहीं कर लेते ।

In case the office of Vice-President is vacant, the Chief Justice of India (or if his office is also vacant, the seniormost judge of the Supreme Court available) acts as the President or discharges the functions of the President.

यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (या यदि उनका पद भी रिक्त है, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध हैं) राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं ।

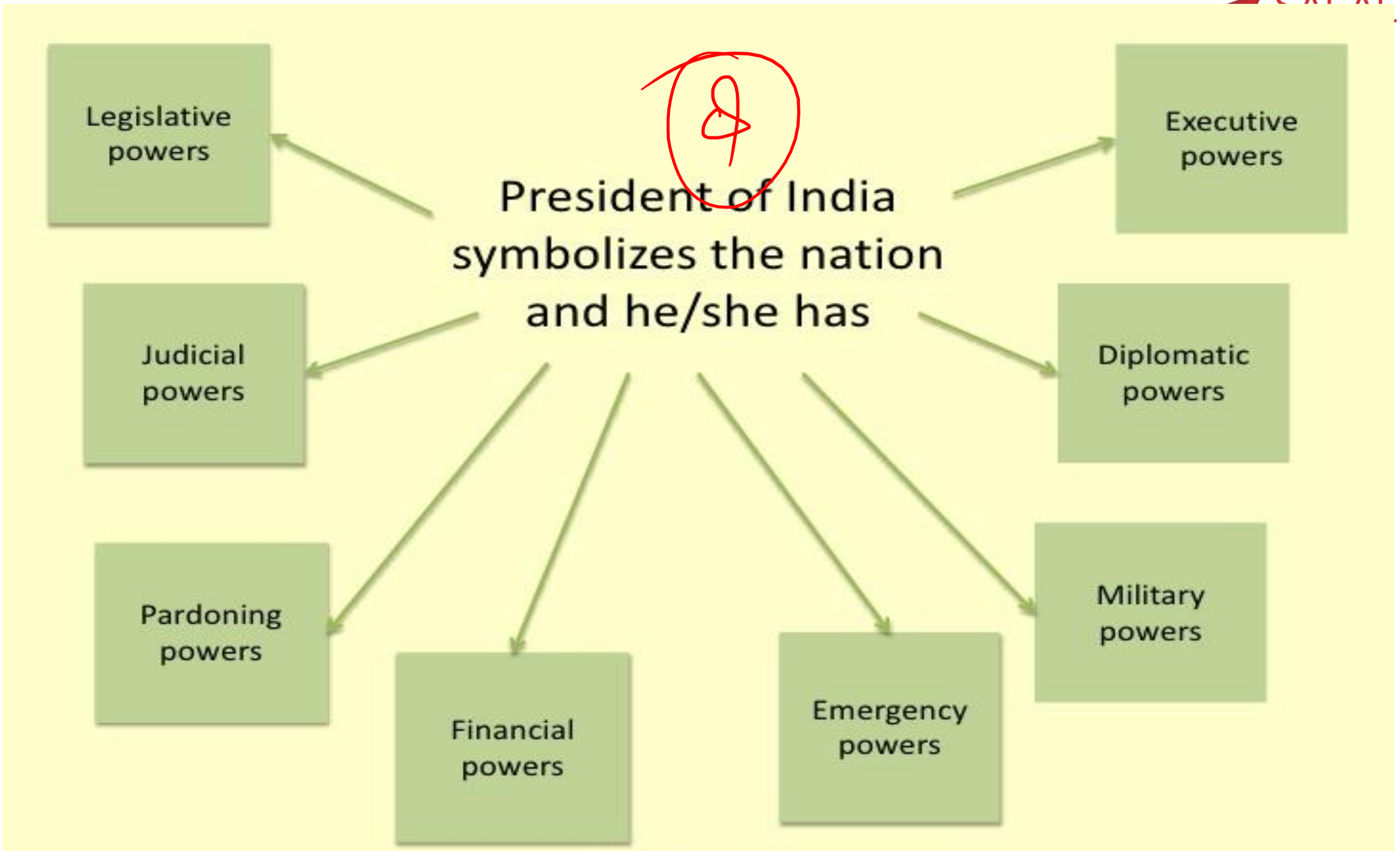
8
President of India symbolizes the nation and he/she has
Legislative powers
Executive powers
Judicial powers
Diplomatic powers
Pardoning powers
Military powers
Financial powers
Emergency powers

Executive Powers

The executive powers and functions of the President are:

1. All executive actions of the Government of India are formally taken in his name.

कार्यकारी शक्तियां

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां और कार्य हैं:

1. भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उनके नाम पर किए जाते हैं।

2.He appoints the prime minister and the other ministers. They hold office during his pleasure.

3.He appoints the attorney general of India and determines his remuneration.

The attorney general holds office during the pleasure of the President.

2. वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं । वे अपनी खुशी के दौरान पद धारण करते हैं ।

3. वह भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करते हैं ।

4.He appoints the comptroller and auditor general of India, the chief election commissioner and other election commissioners, the chairman and members of the Union Public Service Commission, the governors of states, the chairman and members of finance commission, and so on.

4. वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है।

Legislative Powers

1.He can summon or prorogue the Parliament and dissolve the Lok Sabha.

He can also summon a joint sitting of both the Houses of Parliament, which is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.

विधायी शक्तियां

1. वह संसद को बुला सकता है या उसका प्रस्ताव कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है।

वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

2. He can address the Parliament at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year.

3. He nominates 12 members of the Rajya Sabha from amongst persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service.

2. वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में संसद को संबोधित कर सकते हैं और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र ।

3. वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Financial Powers

The financial powers and functions of the President are:

1. Money bills can be introduced in the Parliament only with his prior recommendation.
2. He causes to be laid before the Parliament the annual financial statement (ie, the Union Budget).

राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां और कार्य हैं:

1. धन विधेयकों को संसद में केवल उनकी पूर्व सिफारिश के साथ पेश किया जा सकता है।

2. वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (यानी, केंद्रीय बजट) प्रस्तुत करने का कारण बनता है।

Judicial Powers

1.He appoints the Chief Justice and the judges of Supreme Court and high courts.

2. He can seek advice from the Supreme Court on any question of law or fact.

However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the President.

न्यायिक शक्तियां

1. वह मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
2. वह कानून या तथ्य के किसी भी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Art-72

3.He can grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment, or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence.

3. वह किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, राहत, राहत और छूट, या निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकता है।

Diplomatic Powers

The international treaties and agreements are negotiated and concluded on behalf of the President.

राजनयिक शक्तियां राष्ट्रपति की ओर से अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत और निष्कर्ष निकाला जाता है ।

Military Powers

He is the supreme commander of the defence forces of India.

In that capacity, he appoints the chiefs of the Army, the Navy and the Air Force. He can declare war or conclude peace, subject to the approval of the Parliament.

सैन्य शक्तियां वह भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं।

उस हैसियत से वह सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है।

वह युद्ध की घोषणा कर सकता है या संसद के अनुमोदन के अध लिए शांति समाप्त कर सकता है ।

National Emergency
in India

Emergency Powers

In addition to the normal powers mentioned above, the Constitution confers extraordinary powers on the President to deal with the following three types of emergencies:

(a)National Emergency (Article 352);

(b) President's Rule (Article 356 & 365); and

(c) Financial Emergency (Article 360)

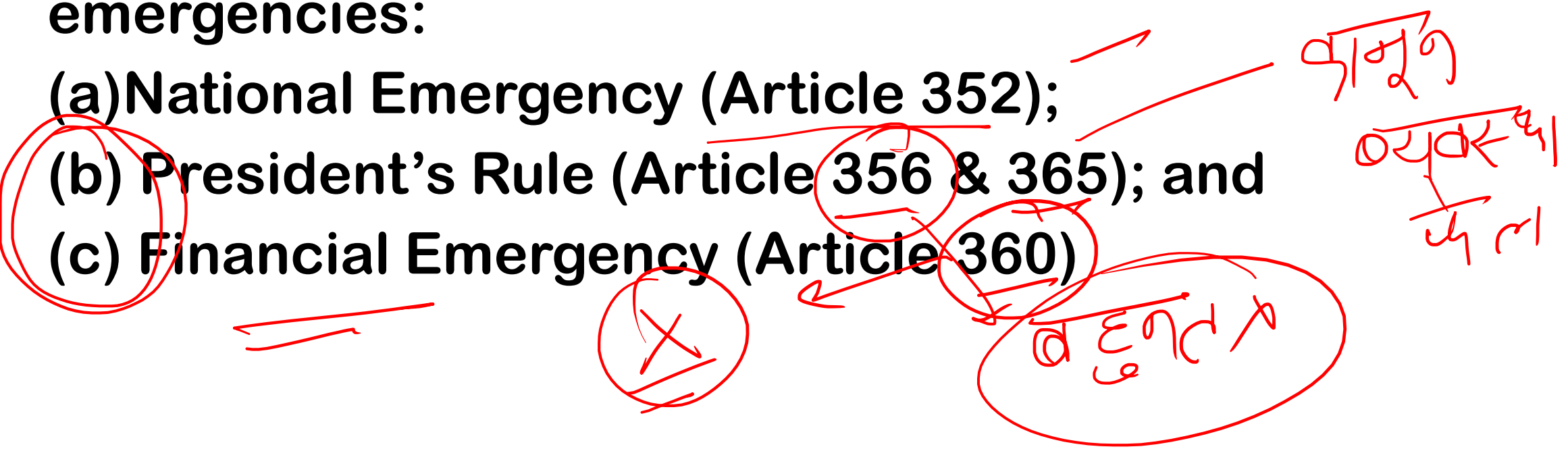

आपातकालीन शक्तियां

उपर्युक्त सामान्य शक्तियों के अलावा, संविधान राष्ट्रपति को निम्नलिखित तीन प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान करता है:

(क) राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352);

(ख) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 और 365); और

(ग) वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

The Emergency provisions are contained in Part XVIII of the Constitution, from Articles 352 to 360.

These provisions enable the Central government to meet any abnormal situation effectively.

आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद ३५२ से ३६० तक निहित हैं ।

ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं।

1.

An emergency due to war, external aggression or armed rebellion (Article 352).

This is popularly known as ‘National Emergency’.

However, the Constitution employs the expression ‘proclamation of emergency’ to denote an emergency of this type.

1. युद्ध, बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह (अनुच्छेद 352) के कारण आपातकाल। इसे 'राष्ट्रीय आपातकाल' के नाम से जाना जाता है।

हालांकि, संविधान इस प्रकार की आपात स्थिति को निरूपित करने के लिए ' आपातकाल की उद्घोषणा ' की अभिव्यक्ति को नियोजित करता है ।

Originally, the Constitution mentioned 'internal disturbance' as the third ground for the proclamation of a National Emergency, but the expression was too vague and had a wider connotation.

Hence, the 44th Amendment Act of 1978 substituted the words 'armed rebellion' for 'internal disturbance'.

मूल रूप से, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए तीसरे आधार के रूप में आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था, लेकिन अभिव्यक्ति बहुत अस्पष्ट थी और इसका व्यापक अर्थ था ।

इसलिए, 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम ने आंतरिक अशांति के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्दों को प्रतिस्थापित किया।

Thus, it is no longer possible to declare a National Emergency on the ground of 'internal disturbance' as was done in 1975 by the Congress government headed by Indira Gandhi.

इस प्रकार, अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है जैसा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा १९७५ में किया गया था ।

Effect on the Fundamental Rights

Articles 358 and 359 describe the effect of a National Emergency on the Fundamental Rights.

Article 358 deals with the suspension of the Fundamental Rights guaranteed by Article 19, while Article 359 deals with the suspension of other Fundamental Rights (except those guaranteed by Articles 20 and 21).

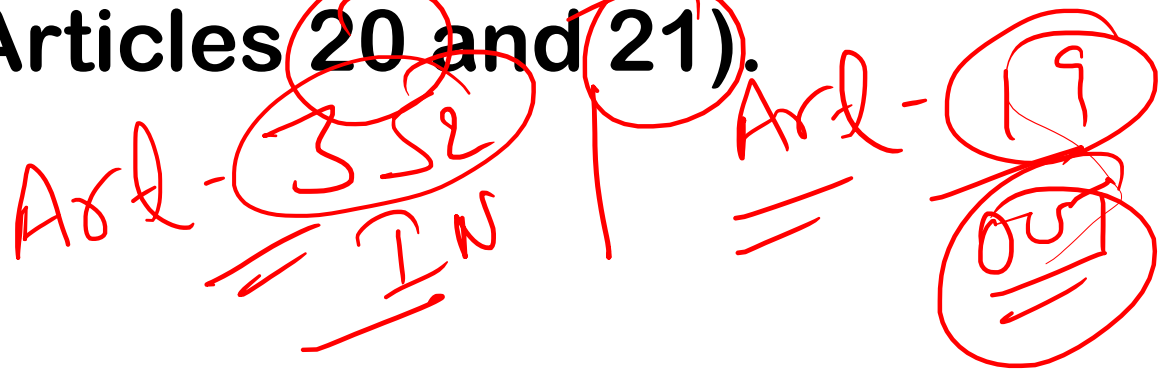

मौलिक अधिकारों पर प्रभाव अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं।

अनुच्छेद ३५८ अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद ३५९ अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित हैं (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) ।

Declarations Made So Far This type of Emergency has been proclaimed three times so far—

1. 1962
2. 1971
3. 1975.

3. Financial Emergency due to a threat to the financial stability or credit of India (Article 360).

Veto Power of the President

A bill passed by the Parliament can become an act only if it receives the assent of the President.

When such a bill is presented to the President for his assent, he has three alternatives (under Article 111 of the Constitution):

राष्ट्रपति की वीटो पावर संसद द्वारा पारित विधेयक तभी एक अधिनियम बन सकता है जब उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। जब इस तरह के एक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पास तीन विकल्प (संविधान के अनुच्छेद १११ के तहत):

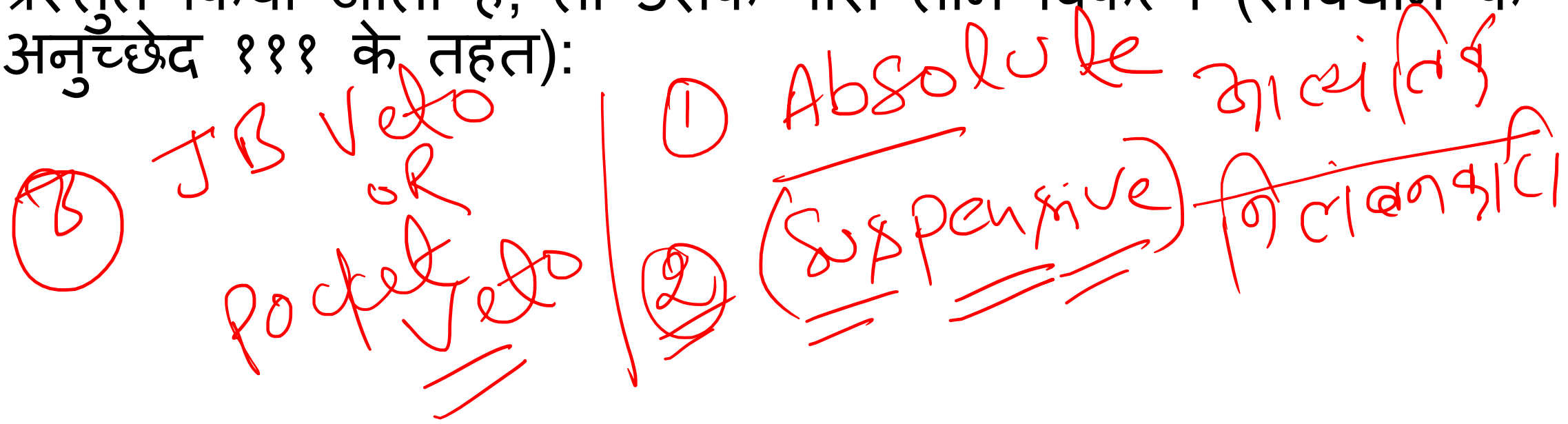

1. He may give his assent to the bill, or
2. He may withhold his assent to the bill, or
3. He may return the bill (if it is not a Money bill) for reconsideration of the Parliament.

However, if the bill is passed again by the Parliament with or without amendments and again presented to the President, the President must give his assent to the bill.

1. वह बिल के लिए अपनी सहमति दे सकता है, या
2. वह बिल के लिए अपनी सहमति रोक सकता है, या
3. वह संसद पर पुनर्विचार के लिए विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) को वापस कर सकता है।

तथापि, यदि विधेयक संसद द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पुन पारित किया जाता है और फिर से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए ।

Ordinance-making Power of the President

Article 123 of the Constitution empowers the President to promulgate ordinances during the recess of Parliament.

These ordinances have the same force and effect as an act of Parliament, but are in the nature of temporary laws.

Time → 6 माह + 6 weeks

अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है।

इन अध्यादेशों में संसद के एक अधिनियम के समान बल और प्रभाव होता है, लेकिन यह अस्थायी कानूनों की प्रकृति में होता है ।